

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India



असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 367] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 31, 1978/श्रावण 9, 1900  
No. 367] NEW DELHI, MONDAY, JULY 31, 1978/SRAVANA 9, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वाली जाती हैं जिससे यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation.

गृह मंत्रालय

भारत के साम्प्रदीय क्षारा 29 जुलाई, 1978 को की गई निम्नलिखित अधिसूचना सर्व-  
साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :—

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1978

का. आ. 479(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 371 व के संदर्भ (८) के द्वारा  
प्रधस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूलिस अधिनियम 1861 (1861 का 5) का  
विरतार रिक्तिकभ राज्य पर तत्काल प्रभावी रूप से इस उपात्तण के अधीन करते हुए  
यह उक्त अधिनियमित में, सिविलग राज्य में एसी विधि जो प्रवृत्त नहीं है, या  
ऐसा कृत्यकारी जो विविधान नहीं है, वे प्रीत नियंत्रण का अधिनियम उस राज्य की

तत्समान प्रवृत्ति विधि, अथवा सत्समान विद्मान कृत्यकारी के प्रति निवेद्य के रूप में किया जाएगा,

परन्तु यह कि यदि ऐसा कोई प्रश्न उठे कि वह तत्समान कृत्यकारी कौन है, या ऐसा कृत्यकारी जो विद्यमान नहीं है, के प्रति निवेद्य का अधिनियम उस राज्य की ऐसा कृत्यकारी कौन होगा, और केस्त्रीय सरकार का निर्णय अनितम होगा।

नीलम संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति

[मि. सं. 11013/6/78-सिक्किम]

एम. एस. कम्पानी, अपर सचिव

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

The following notification made by the President of India on the 29th July, 1978 is published for general information—

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 1978

**S.O. 479(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (n) of article 371F of the Constitution, the President hereby extends to the State of Sikkim, with immediate effect, the Police Act, 1861, (5 of 1861), subject to the modification that any reference in the said Act to a law not in force, or to a functionary not in existence, in the State of Sikkim shall be construed as a reference to the corresponding law in force, or to the corresponding functionary in existence, in that State :

Provided that if any question arises as to who such corresponding functionary is, or if there is no such corresponding functionary, the Central Government shall decide as to who such functionary will be and the decision of the Central Government shall be final.

NEELAM SANJIVA REDDY, President

[F. 11013/6/78-SKM]

M. L. KAMPANI, Addl. Secy.